



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2002/26 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, अप्रैल, 2002

संख्या गृह(ए)एफ(13) 6/2001.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जहालमा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति में पुलिस चौकी के निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3 पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता [उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)], लाहौल स्थित, केलंग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : लाहौल एवं स्पिति

उप-तहसील : उदयपुर

गांव	खसरा नं०	रकबा (बीघों में)
जहलमा	60	1 00 00
किन्ता	1	1 00 00

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अप्रैल, 2002

संख्या टी0 सी0 पी0-एफ0(1) -1/95.—यत्तः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 (सी0 सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मौजा पट्टी रिहाणा, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के मलबे हेतु भूमि का अर्जन अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त क्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : शिमला

गांव	खसरा नं०	रकबा (बीघों में)
मोजा पट्टी रिहाणा	29/1	1 08
	34/1	0 01
	36/1	0 02
	37/1	0 01
	39	0 10
	44/1	0 05
कुल ..	6	2 07

आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित/-
वित्तियुक्त एवं सचिव।

